

महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)** ने बताया कि वर्ष 2017-18 और 2022-23 के बीच भारत के लगभग सभी राज्यों में **महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)** में वृद्धि हुई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक वृद्धि देखी गई है।

मुख्य बटु

- महिला LFPR पर मुख्य नषिकर्षः
- क्षेत्रीय वविधिताएँ:
 - बहिर, पंजाब और हरयाणा में लगातार बहुत कम महिला LFPR की सूचना दी गई।
 - सबसे अमीर राज्यों में शामिल होने के बावजूद, पंजाब और हरयाणा में महिला LFPR कम है, जबकि सबसे गरीब राज्य बहिर भी पीछे है।
- वकिसः
 - ग्रामीण क्षेत्रों में महिला LFPR वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान 24.6% से बढ़कर 41.5% हो गई।
 - इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में महिला LFPR 20.4% से बढ़कर 25.4% हो गई।
 - समग्र प्रवृत्तयिह है कि अवैतनकि पारवारकि श्रमकिों या घरेलू सहायकों को हटाने के बाद भी वृद्धि स्थिरि बनी रही।
- अन्य रुझानः
- वैवाहकि स्थितिः
 - वविहति पुरुष वभिनिन राज्यों और आयु समूहों में उच्च LFPR प्रदर्शति करते हैं।
 - वविह से महिला LFPR में उल्लेखनीय कमी आती है, वशिष रूप से शहरी क्षेत्रों में।
- आयु गतशीलताः
 - महिला LFPR एक घंटीनुमा वकर बनाती है, जो 30-40 वर्ष की आयु में चरम पर होती है तथा उसके बाद तेज़ी से घटती है।
 - पुरुष LFPR 30-50 वर्ष की आयु के बीच लगभग 100% रहता है और उसके बाद धीरे-धीरे कम होता जाता है।
- राज्यवार अवलोकनः
 - उत्तरी राज्यः पंजाब और हरयाणा में महिला LFPR कम दर्ज की गई।
 - पूर्वी राज्यः ग्रामीण बहिर में LFPR सबसे कम था, लेकिन इसमें सुधार हुआ, वशिष रूप से वविहति महिलाओं के मामले में।
 - पूर्वोत्तर राज्यः ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति देखी गई, जिसमें नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश अग्रणी रहे।
- सरकारी योजनाओं का प्रभावः
- मुद्रा ऋण
- डरोन दीदी योजना
- दीनदयाल अंतयोदय योजना
 - ये योजनाएँ महिलाओं के नेतृत्व वाले वकिस पर ज़ोर देती हैं, जो कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा को दर्शाती हैं।
- महिला LFPR में वृद्धि, वशिष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, रोजगार प्रवृत्तयिों में उल्लेखनीय परिवर्तन को रेखांकति करती है। इस वृद्धिको बनाए रखने और बढ़ाने के लयि आगे का वशिलेषण और सरकारी सहायता आवश्यक होगी।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)

- यह एक गैर-संवैधानकि, गैर-सांवधिकि, स्वतंत्र नकियाय है जिसका गठन भारत सरकार, वशिष रूप से प्रधान मंत्री को आर्थिक और संबधति मुद्दों पर सलाह देने के लयि कयिा गया है।
- यह परिषद तटस्थ दृष्टिकोण से भारत सरकार के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य करती है।
- यह मुद्रासफ़ति, माइक्रोफाइनेंस और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देता है।

- प्रशासनिक, संभार-तंत्र, योजना और बजटीय उद्देश्यों के लिये [नीति आयोग EAC-PM](#) के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- **आवधिक रिपोर्ट:**
 - वार्षिक आर्थिक परिदृश्य
 - अर्थव्यवस्था की समीक्षा

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/increase-of-female-labour-force-participation-rate>

